Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January 2024 5(1), 1969–1975

HISTORY, IDEOLOGICAL ASPECTS AND FUTURE VISION OF AAM AADMI PARTY

आम आदमी पार्टी का इतिहास, सैद्धांतिक पक्ष और भविष्य की दृष्टि

Rakesh Kumar Jaiswal [1]

[1] Assistant Professor, Department of Political Science, Government College, Badaun, U.P.

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.4731

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: Aam Aadmi Party, as an Indian political party, was formally established on 26 November 2012. Anna Hazare, the prominent fasting leader of the anti-corruption movement, and his activist Arvind Kejriwal had a disagreement on the issue of whether or not to politicize the 'India Against Corruption' (IAC) movement. In India, political corruption and instability can be seen throughout the government system. Arvind Kejriwal took the controversial decision to fight the corrupt government system by directly joining politics. Exhibiting a bold and democratic attitude, Aam Aadmi Party demanded that India, as a democratic country, should become a nation with transparency, accountability, fair legislative system and common participation in government affairs. In the 2013 Delhi Assembly election, Aam Aadmi Party became the second largest vote-getter in the Delhi Assembly by winning 28 out of 70 seats. An important part of its agenda was to pass the Jan Lokpal Bill and make it a law in India. Due to the uncooperative attitude of other major political parties in India, Aam Aadmi Party resigned after being in government for just 49 days. In 2015, Aam Aadmi Party again won a historic victory by securing 67 out of 70 seats in Delhi Assembly with the resolve to clean up politics.

Hindi: आम आदमी पार्टी, एक भारतीय राजनीतिक पार्टी के रूप में, 26 नवंबर 2012 को औपचारिक रूप से स्थापित की गई थी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख अनशनकारी नेता अन्ना हजारे और उनके कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हो गया कि 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' (IAC) आंदोलन का राजनीतिकरण किया जाए या नहीं। भारत में, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अस्थिरता पूरी सरकारी व्यवस्था में देखी जा सकती है। अरविन्द केजरीवाल ने राजनीति में सीधे शामिल होकर भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था से लड़ने का विवादास्पद निर्णय लिया। एक साहसिक और लोकतांत्रिक रवैये का प्रदर्शन करते हुए, आम आदमी पार्टी ने मांग की कि भारत, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्ष विधायी प्रणाली और सरकारी मामलों में आम भागीदारी वाला राष्ट्र बने । 2013 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीतकर दिल्ली विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी वोट पाने वाली पार्टी बन गई। इसके एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में जन लोकपाल विधेयक पारित कर कानून बनाना था। भारत में अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के असहयोगी रवैये के कारण आम आदमी पार्टी ने सरकार में मात्र 49 दिन रहने के बाद ही इस्तीफा दे दिया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने राजनीति को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें हासिल करके फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल की।

Keywords: Aam Aadmi Party, History, Future, Ideological Side, आम आदमी पार्टी, इतिहास, भविष्य, सैद्धांतिक पक्ष

प्रस्तावना

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के आमंत्रण पर दिल्ली के मतदाताओं से राय लेकर 28 दिसम्बर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने 7 मंत्रियों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। विश्वास मत प्रस्ताव पर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार का समर्थन किया। सरकार बनाते ही पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र के वादे पूरे करने शुरु किए। विशेष सुरक्षा और लाल बत्ती वाली गाड़ी लेने से मना किया। 31 दिसम्बर को बिजली की कीमतों में अप्रैल तक आधे की छूट देने की घोषणा की। बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट कराने की व्यवस्था की। बीस किलोलीटर पानी मुफ्त देने की घोषणा की। इस सरकार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से अनेक मामलों पर अवरोध का सामना करना पड़ा।

बलात्कार एवं अन्य अपराध की घटनाओं पर पुलिस के कुछ अधिकारियों का तबादला करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय जाकर धरना देने की कोशिश की। इसमें अड़चने डालने पर रेल भवन के पास सड़क पर केजरीवाल सरकार धरने पर बैठ गई। बाद में उपराज्यपाल के द्वारा पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने के बाद सरकार वापस काम पर लौटी। खिड़की एक्सटेंसन में कानून मंत्री सोमनाथ भारती की भूमिका भी विवादित रही। फरवरी में अरविन्द केजरीवाल ने अपने निगरानी विभाग को प्राकृतिक गैस का दाम अनियमित रूप से बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी और एम॰ वीरप्पा मोइली सहित कई प्रभावी लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।केजरीवाल सरकार ने 13 फ़रवरी से विधान सभा सत्र बुलाकर जनलोकपाल और स्वराज्य विधेयक पारित करने की घोषणा की। जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने को लेकर उनका केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल से टकराव की स्थिति पैदा हो गई। लेफ्टिनेंट राज्यपाल नजीब जंग इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को जरूरी बताते रहे, जबकि केजरीवाल सरकार विधान सभा में विधेयक पास करने के संवैधानिक अधिकार पर डटी रही। 13 जनवरी के हंगामेदार सत्र के बाद 14 फ़रवरी के सत्र में राज्यपाल ने विधेयक को असंवैधानिक बताने का संदेश विधानसभा अध्यक्ष को भेजा और विधेयक पेश करने से पहले संदेश को सूचित करने को लिखा। इस संदेश के बाद कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने विधेयक प्रस्तुत करने का मिलकर विरोध किया। जन लोकपाल पास करना तो दूर उसे प्रस्तुत भी न हो पाने के बाद अरविन्द केजरीवाल ने 14 फ़रवरी को इस्तीफा दे दिया। इस कारण दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा।

सार्वजनिक परिवहन

सार्वजनिक परिवहन में सुधार: आम आदमी पार्टी (आप) ने सार्वजनिक परिवहन में काफी सुधार करने का वादा किया था लेकिन केजरीवाल का वितरण डीटीसी के मौजूदा बेड़े में एक भी बस नहीं जोड़ सकी। अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के वादे को पूरा करने की कोई प्रगति नहीं हुई थी

सार्वजनिक क्षेत्रों में वाई-फाई: यह एक ऐसा वादा था जो दिल्ली के लोगों को सबसे अधिक आकर्षित कर रहा था।

"हम दिल्ली में पूरी तरह से वाई-फाई उपलब्ध कराएंगे ... वाई-फाई दिल्ली के सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएगी। इंटरनेट और दूरसंचार कंपनियों से संपर्क किया गया है और उनके साथ परामर्श करके एक उच्च स्तरीय व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। " लेकिन दो साल बाद भी, राष्ट्रीय राजधानी भी नि: शुल्क वाई-फाई सेवाओं का इंतजार करती रही ।

सम्पूर्ण दिल्ली में 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए: यह एक और वादा था, जो आम आदमी पार्टी पूरी करने में नाकाम रही। पार्टी के दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा था, राष्ट्रीय राजधानी विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी प्राप्त करेगी, लेकिन दिल्लीवासियों को इसके कार्यान्वयन के लिए इंतजार करना पड़ा ।

गठन के समय AAP ने कहा था कि भारत के संविधान और इसकी प्रस्तावना में शामिल समानता और न्याय का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है और भारत की स्वतंत्रता ने एक दमनकारी विदेशी शक्ति की गुलामी की जगह एक राजनीतिक अभिजात वर्ग की गुलामी ने ले ली है। इसने दावा किया कि भारत के आम लोगों की बात अनसुनी और अनदेखी की जाती है, सिवाय तब जब यह राजनेताओं के अनुकूल हो। आप का लक्ष्य सरकारी जवाबदेही के संचालन के तरीके को उलटना है और पार्टी स्वराज की गांधीवादी समाजवादी अवधारणा की व्याख्या को एक सिद्धांत के रूप में लेती है। इसका मानना है कि स्वराज के माध्यम से सरकार उच्च अधिकारियों के बजाय सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। स्वराज मॉडल स्वशासन, समुदाय निर्माण और विकेंद्रीकरण पर जोर देता है।

केजरीवाल ने कहा है कि आप विचारधाराओं से निर्देशित होने से इनकार करती है और वे व्यवस्था को बदलने के लिए राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा, "हम आम आदमी हैं। अगर हमें अपना समाधान वामपंथ में मिलता है, तो हम इसे वहां से उधार लेने में खुश हैं। अगर हमें अपना समाधान दक्षिणपंथ में मिलता है, तो हम इसे वहां से उधार लेने में खुश हैं।" केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा के 3 स्तंभों को आगे रखा है: कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और मानवता।

पार्टी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खत्म करने और समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह दोनों को वैध बनाने की वकालत करती है। पार्टी को लोकलुभावन और मध्यमार्गी भी माना जाता है।

AAP सरकार के कार्यकाल के दौरान, दिल्ली ने भारत की स्टार्ट-अप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। आप सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान समय-समय पर दिल्ली में विभिन्न स्टार्ट-अप नीतियों को बढ़ावा दिया है।

पृष्ठभूमि

अरविंद केजरीवाल, एक सामाजिक कार्यकर्ता, पारदर्शी और भागीदारी वाली शासन प्रणाली के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि भारत में हजारों लोग भ्रष्टाचार और खराब आर्थिक विकास के कारण गरीबी में जी रहे हैं। केजरीवाल ने नई दिल्ली में एक सहायक आयुक्त के रूप में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में काम किया। शुरू से ही, वह अक्सर अपने सहयोगियों के साथ राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर असंतोष की भावना के साथ चर्चा करते थे। उनके दृष्टिकोण में, "यदि आप भ्रष्ट हैं, तो आप मुख्यधारा में हैं। यदि आप ईमानदार हैं, तो आप हाशिए पर हैं।" 1998 में, केजरीवाल

ने 'कबीर' पंजीकृत किया, जो दिल्ली में कई संघों को लोगों को बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिलों का भुगतान करने से रोकने के लिए राजी करने के लिए एक मंच था। दिसंबर 1999 में, उन्होंने शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'परिवर्तन' या 'परिवर्तन' नामक एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शुरू किया। 2001 में, उन्होंने 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आरटीआईए) की पैरवी की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के भारतीय समकक्ष है। जो 2005 में कानून बन गया। 2006 में, उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करके जमीनी स्तर के आंदोलन 'परिवर्तन' में उनकी भागीदारी को स्वीकार करते हुए, उभरते नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में, उसी वर्ष, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित नौकरी (आईआरएस) का त्याग किया और एक गैर सरकारी संगठन, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन (पीसीआरएफ) को पचास हजार डॉलर की मैग्सेसे पुरस्कार राशि दान कर दी। 2007 तक, केजरीवाल ने सरकार पर लोकपाल नामक एक नया भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण स्थापित करने का दबाव डाला; संस्कृत में इसका अर्थ है 'जनता का रखवाला'। शासन व्यवस्था की घोर दुष्टता से क्षुब्ध केजरीवाल यह समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर भ्रष्टाचार के ढेरों प्रमाण छपते हैं जो लोगों को चुनौती देते हैं कि 'यदि आप कुछ कर सकते हैं तो करें। हम देश को लूटते रहेंगे।' 2010 में पहली बार केजरीवाल ने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया जो बाद में टकराव में बदल गया। सबसे पहले केजरीवाल राष्ट्रमंडल खेलों की घोर कुटिलता से क्षुब्ध थे और फिर उन्होंने सरकार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को समृद्ध करने के लिए प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। हालांकि अंबानी ने इस आरोप का खंडन किया। केजरीवाल को जन लोकपाल आंदोलन या अन्ना आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक माना जाता है, जिसने 2011 में देश को हिलाकर रख दिया था "आपसी भ्रष्टाचार वह है जहाँ करदाता और कर अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं" और "जबरन वसूली भ्रष्टाचार वह है जहाँ आपको वैध काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है।" 2011 में, केजरीवाल को न्यू दिल्ली टेलीविज़न द्वारा वर्ष के दो भारतीयों में से एक नामित किया जा रहा था। उसी वर्ष, केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भूख हड़ताल की श्रृंखला की पहली व्यवस्था की, संसद को भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित करने के लिए मजबूर किया और जन लोकपाल विधेयक का समर्थन करने के लिए दिल्ली में भारी भीड़ जुटाई, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए लोकपाल की स्थापना करना था। उन्होंने क्रिकेट विश्व कप के अंत और एक घरेलू टूर्नामेंट, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत के बीच हड़ताल का समय तय किया। पांच दिवसीय रैली में, उन्होंने चतुराई से अन्ना हजारे को केंद्र में रखा। रैली में हजारों लोग उमड़ पड़े

AAP और राजनीतिक क्रांति

हालाँकि हजारे, दलीय राजनीति में अपने अविश्वास के कारण, चाहते थे कि आंदोलन राजनीतिक रूप से असंबद्ध रहे। केजरीवाल (हजारे के दाहिने हाथ) का मानना था कि केवल प्रदर्शन से व्यवस्था में वांछित परिवर्तन नहीं हो सकता। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच विभाजन ने आम आदमी पार्टी (आप) को जन्म दिया। हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने केजरीवाल के लिए एक राजनीतिक पार्टी स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थिति तैयार की थी। इस असंतोष ने बाद में एक नई राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया- आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को साफ करने की प्रतिज्ञा के साथ राजनीतिक परिदृश्य में उभरी। आप भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों से उभरी, जो 2011 में एक अनुभवी गांधीवादी प्रदर्शनकारी अन्ना हजारे द्वारा की गई भूख हड़ताल से प्रेरित थी। केजरीवाल, उनके लेफ्टिनेंट ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए हजारों लोगों को इकट्ठा किया।

सर्वहारा-पूंजीपति वर्ग के द्वंद्व से बाहर निकलकर आप सामाजिक सक्रियता का मंच बन गई। आप के उदय के साथ भारतीय राजनीति का पारंपरिक चेहरा बदल गया है। भारतीय मध्यम वर्ग भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत जोश के साथ उठाता है। आप का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जिस तरह पार्टी का घोषणापत्र भी राजनीति को अंदर से साफ करने का है। आप कार्यकर्ताओं ने सफेद गांधी टोपी पहनी हुई थी, जिस पर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में हिंदी में 'मैं आम आदमी हूं' लिखा हुआ था। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ने 70 में से 28 सीटें जीतीं और 27 विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला सभाएं आयोजित करने की घोषणा की, जहां आप उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव जीता था। आयकर विभाग में पूर्व सहायक आयुक्त और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी विशाल प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। शपथ लेने के तुरंत बाद केजरीवाल ने लोकपाल विधेयक का राज्य संस्करण पेश किया। लोकपाल विधेयक के कार्यान्वयन में विफलता के कारण, AAP ने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और अन्य राजनीतिक दलों पर राजनीतिक पक्षाघात का आरोप लगाया। "एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता के रूप में, केजरीवाल ने बहुत ही प्रभावशाली और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। हालाँकि, एक राजनेता के रूप में, उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो अपेक्षित था। उनके अचानक इस्तीफे ने सरकार में प्रभावी ढंग से काम करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाया, भारत की जटिल और निराशाजनक नौकरशाही की तो बात ही छोड़िए।" ।

सरकार छोड़ने के लिए माफ़ी मांगने के बाद, AAP ने 2014 में भारत के 16वें लोकसभा की आम चुनाव के लिए अभियान शुरू किया, जिसे 1977 के बाद से भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना गया था। राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय लोकपालों को कवर करने वाले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को जनवरी 2014 में केंद्र सरकार द्वारा लंबी चर्चाओं और परिवर्तनों के बाद मंजूरी दी गई थी। 2015 के दिल्ली चुनाव में, केजरीवाल ने अभियान के लिए नारा अपनाया, "पांच साल केजरीवाल", "केजरीवाल के लिए पांच साल" मतदाताओं को यह बताने के लिए कि वे पांच साल तक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। AAP ने 2015 में दिल्ली की छठी विधानसभा में 70 में से 67

सीटें हासिल करके शानदार जीत हासिल की। दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से भाजपा ने केवल 3 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने कोई सीट नहीं जीती। AAP भारतीय राजनीति में एक वास्तविक खेल परिवर्तक साबित हुई।

स्वराज (स्व-शासन)

स्वराज का अर्थ है आत्म-संयम और दूसरों के अहिंसक अनुनय पर आधारित स्व-शासन ताकि समूह-जीवन भी स्व-शासित और आत्मनिर्भर बन सके। गांधीजी ने अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज' (भारतीय गृह शासन) 1909 में लिखा है, भारत अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उत्साहित है ताकि भारत के मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने के लिए देशी (स्व-शासन) सरकार स्थापित की जा सके। लेकिन यह केवल शाही शक्ति का प्रतिस्थापन था, न कि स्वराज की स्थापना। गांधी ने टिप्पणी की: "अंग्रेजों ने भारत नहीं लिया; हमने उन्हें यह दिया है। वे अपनी ताकत के कारण भारत में नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें रखते हैं।" गांधी ने स्वराज के लोकप्रिय अर्थ, यानी स्वशासन को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन उनके लिए स्वराज का वास्तविक अर्थ इससे परे जाना चाहिए और इस लोकप्रिय अर्थ का आधार बनना चाहिए। 'हिंद स्वराज' में गांधी के स्वराज का अर्थ व्यक्तिगत स्तर पर स्वशासन की स्वतंत्रता या सभी के लिए खुद पर शासन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस क्षमता को हासिल करने की प्रक्रिया लंबी है। गांधी के अपने शब्दों में स्वराज का अर्थ: ...अगर हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो भारत स्वतंत्र है। स्वराज का अर्थ है "जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं। इसलिए, यह हमारी हथेली में है..." (ब्राउन, 1984)) वास्तविक अर्थ में स्वराज का अर्थ है 'खुद पर शासन करना सीखना या स्वशासन की योग्यता प्राप्त करना। जो ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसे स्वतंत्र या स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला कहा जाता है। इस प्रकार गांधी के लिए स्वतंत्रता और स्वशासन (स्वराज) न केवल एक दूसरे के अनुरूप हैं, बल्कि एक और एक ही हैं। गांधी की तरह केजरीवाल ने भी एक पुस्तक 'स्वराज' लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि "हमारे देश में मूल समस्या यह है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमें लोकतंत्र चाहिए।" केजरीवाल प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भ्रष्ट हैं।

केजरीवाल का मानना था कि लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करती है और वोट डालने के बाद पाँच साल के लिए निर्णय लेने से पहले लोगों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है (जैफरलॉट, 2014) केजरीवाल के अनुसार, भारत में अत्यधिक विनियमन, जटिल करों और लाइसेंसिंग प्रणाली के कारण लगभग सभी सरकारी क्षेत्र पारदर्शिता और आम भागीदारी के बिना काम करते हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसने आम लोगों के लिए जीवन कठिन बना दिया है। शासन व्यवस्था में आम लोगों को सशक्त बनाने से जबरदस्त विकास होगा।

सत्ता के केन्द्रों को दिल्ली से हटाकर अन्य राजधानियों और गांवों में ले जाना चाहिए। केजरीवाल के अनुसार, यद्यपि 1947 में औपचारिक हस्ताक्षर के बाद अंग्रेज चले गए और सत्ता पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो गया। 1947 के बाद भारत पर दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों से शासन किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि भारत के लोग स्वराज चाहते हैं; ऐसा स्वतंत्र भारत जिसमें लोग शासन करेंगे। ताकि न्याय हो। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन व्यवस्था बनी रही। समय बीतने के साथ भ्रष्टाचार और अन्याय हावी हो गया है। "पैसा आम आदमी की बजाय भ्रष्ट लोगों की जेब में जाता है।" (केजरीवाल, 2012) अगर स्वराज होगा, तो "हम अपने गांवों, अपने शहर और अपने समुदाय से जुड़े फैसले ले सकेंगे।" संसद और विधानसभाओं में बनने वाले कानून भी हमारी सहमति और भागीदारी से ही बनेंगे। (केजरीवाल, 2012) यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, जहां शासन की शक्ति और लोकतंत्र के अधिकार स्थानीय लोगों या समुदाय के हाथों में होंगे।

उद्देश्य

आम आदमी पार्टी का इतिहास

आम आदमी पार्टी का सैद्धांतिक पक्ष

आम आदमी पार्टी की भविष्य की दृष्टि

परिणाम

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013

4 दिसम्बर 2013 को हुए दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा। उसने पूरी दिल्ली के लिये चुनावी घोषणापत्र तैयार करने के साथ ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये अलग-अलग घोषणापत्र तैयार किया।[8]

दिल्ली चुनाव के पहले पार्टी को कई विवादों का सामना करना पड़ा। भारत सरकार के गृहमन्त्री, सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी के विदेशी दान की जाँच कराने की बात कही। पार्टी ने दान राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा पार्टी वेवसाइट पर पहले से ही सार्वजनिक होने की बात कही और अन्य राजनीतिक दलों को भी अपने चन्दे को सार्वजनिक करने की चुनौती दी।

दिल्ली विधान सभा चुनाव के कुछ पहले एक मीडिया पोर्टल द्वारा आम आदमी के विधायक पद के उम्मीदवारों का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें उन पर ग़ैर-ईमानदार होने के आरोप लगाये गये। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर स्टिंग वीडियो में कई महत्वपूर्ण भागों को काट-छाँट कर प्रस्तुत करने का आरोप लगाया और मीडिया पोर्टल के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की।

6 दिसम्बर को घोषित हुए परिणाम में ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में पार्टी 28 सीटों पर विजयी रही। 32 विधान सभा क्षेत्रों की विजेता भारतीय जनता पार्टी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अरविन्द केजरीवाल ने सत्तारूढ़ी कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान मुख्यमन्त्री शीला दीक्षित (कांग्रेस) को लगभग 25,000 वोटों से पराजित किया।[9] और कांग्रेस केवल 8 सीटों पर सिमट गयी।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भाजपा द्वारा सरकार बनाने से मना करने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता अरविन्द केजरीवाल को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। 28 दिसम्बर को कांग्रेस के समर्थन से पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनायी। अरविन्द केजरीवाल सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने।

लोकसभा चुनाव 2014

AAP ने 2014 के भारतीय आम चुनाव में 434 उम्मीदवार उतारे, जिसमें उसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। इसने माना कि इसका समर्थन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पर आधारित था और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है। पार्टी ने बताया कि उसकी फंडिंग सीमित थी और केजरीवाल की ओर से स्थानीय दौरों की बहुत अधिक मांगें थीं। इरादा चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की संभावना को अधिकतम करने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का था। नतीजा यह हुआ कि AAP के चार उम्मीदवार जीते, सभी पंजाब से। परिणामस्वरूप, AAP पंजाब में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई। पार्टी को देश भर में पड़े सभी वोटों का 2% प्राप्त हुआ और उसके 414 उम्मीदवारों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक-छठा वोट हासिल करने में विफल रहने के कारण अपनी जमानत जब्त कर ली। हालाँकि पार्टी को दिल्ली में 32.9 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन वह वहाँ कोई भी सीट जीतने में असफल रही।

AAP संयोजक, अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा, लेकिन 371,784 (20.30%) वोटों के अंतर से हार गए और बसपा, कांग्रेस, सपा से आगे दूसरे स्थान पर रहे।

चुनाव के तुरंत बाद, शाज़िया इल्मी (पीएसी सदस्य) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेन्द्र यादव ने अपनी पार्टी के सदस्यों को लिखे एक पत्र में केजरीवाल की नेतृत्व शैली की आलोचना की।

8 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, पार्टी और केजरीवाल ने इन मतभेदों को स्वीकार किया और स्थानीय और साथ ही राष्ट्रीय निर्णय लेने में अधिक लोगों को शामिल करने के लिए "मिशन विस्तार" (मिशन विस्तार) शुरू करने की घोषणा की।

पंजाब विधानसभा चुनाव 2017

पहली बार, आप ने 2017 गोवा विधानसभा चुनाव और 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा। गोवा में AAP कोई भी सीट नहीं जीत सकी और 39 में से 38 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में विफल रहे।

2017 पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए, लोक इंसाफ पार्टी ने AAP के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को AAP गठबंधन कहा गया और समाचार चैनलों पर इसे AAP+ के रूप में दर्शाया गया। इसने कुल 22 सीटें जीतीं, जिनमें से दो लोक इंसाफ पार्टी ने और बाकी बीस आप ने जीतीं।

लोकसभा चुनाव 2019

2014 के भारतीय आम चुनाव के विपरीत, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने कुछ राज्यों की सीमित सीटों और दिल्ली, गोवा, और पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरियाणा राज्य में, आप ने तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। पीएसी ने केरल में सीपीआई (एम) के लिए समर्थन और प्रचार करने का भी निर्णय लिया। पार्टी ने अपना पहला ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मैदान में उतारा। आप ने संगरूर का केवल 1 निर्वाचन क्षेत्र जीता।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

चुनाव लड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा चलाए गए जोरदार अभियान के बाद, 8 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। वोटों की गिनती और उसके बाद नतीजों की घोषणा 11 फरवरी को हुई।

आम आदमी पार्टी ने सरकार बरकरार रखी क्योंकि पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतीं। अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। परिणामों के अनुसार, पार्टी का वोट शेयर 53.5% था।

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022

जनवरी 2021 में, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आप 2022 में छह राज्यों में चुनाव लड़ेगी। ये छह राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और पंजाब थे। पार्टी ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराकर भारी जीत हासिल की और राज्य पार्टी संयोजक भगवंत मान ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

AAP सरकार की उपलब्धियाँ

आधी कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है;

प्रत्येक घर में हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी पहुँचाया जाता है;

भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन हेल्पलाइन नंबर 1031 के साथ पहले से ही शुरू है;

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और कॉलोनियों के पुनर्वास के लिए कदम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं;

दिल्ली को वाई-फाई सिटी बनाने के लिए काम शुरू किया गया है।

दिल्ली के स्कूलों में अब कोई डोनेशन और कैपिटेशन फीस नहीं ली जाती है;

अत्यधिक फीस वसूलने वाले 200 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं;

सरकार ने ई-राशन कार्ड ऑनलाइन जारी करना शुरू कर दिया है;

लाल बत्ती संस्कृति बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी कारों पर लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर रहे हैं;

सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट तैयार की जानी है;

दिल्ली में नए थर्मल पावर प्लांट बनाए जाने हैं;

आरटीओ कार्यालयों में भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है।

सीएम अरविंद केजरीवाल सहित विभिन्न आप नेताओं द्वारा नियमित रूप से जनता दरबार लगाए जा रहे हैं।

और, पानी के कनेक्शन के बिना क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।

निष्कर्ष

तीन साल पहले, केजरीवाल और उनकी आप पार्टी दिल्ली सरकार में आने से पहले ही सरकार और राजनेताओं पर लगातार हमले करने के कारण चर्चा में रही है। पार्टी ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी शुरुआत की और दिल्ली सरकार की स्थापना के बाद पार्टी ने एक भी दिन नहीं गंवाया, लेकिन जन लोकपाल विधेयक लागू न होने के कारण उसे सरकार में आने के कुछ दिनों बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जवाबदेही और प्रभावकारिता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। 2015 में फिर से पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीटें हासिल कीं। तमाम आलोचनाओं के बाद, आप भारतीय लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। नीतियां आम आदमी के परामर्श से और उसके लाभ के लिए बनाई जानी चाहिए। आप जन लोकपाल विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर उपाय है।

संदर्भ

अग्रवाल, अरुण कुमार (2007)। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार: भारत का एक मामला। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 68(2), 325-336।

आशु, पसरीचा। (2010)। सहमतिपूर्ण लोकतंत्र गांधी ऑन स्टेट, पावर एंड पॉलिटिक्स। कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, भारत।

अंजनेयुलु, बी। (2003)। गांधी का 'हिंद स्वराज' - स्वराज, स्वदेशी तरीका। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 64(1/2), 33-44।

भट्टाचार्य, सुदीप। (2015)। वर्षों से: समकालीन मुद्दों पर मेरी टिप्पणियों का संकलन। एजुक्रिएशन पब्लिशिंग, भारत।

मुहम्मद सोहेल और इज़्ज़त रज़िया 82 जर्नल ऑफ़ इंडियन स्टडीज़

ब्राउन, सी। (1984)। स्वराज, स्वतंत्रता का भारतीय आदर्श: एक राजनीतिक या धार्मिक अवधारणा? धार्मिक अध्ययन, 20(3), 429-441.
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2015. (2015). ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. से लिया गया.
द्विवेदी, अरविंद मोहन और रोशन, रजनीश. (2014). चुंबकीय व्यक्तित्व अरविंद केजरीवाल. डायमंड बुक्स पब्लिशर पब्लिशर्स, नई दिल्ली.
ग्रीन, डंकन. (2016). कैसे बदलाव होता है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनाइटेड किंगडम.
गोधवानी, राकेश. (2014). क्या कहना है और कब चुप रहना है. रैंडम हाउस इंडिया, भारत.
जैफरलॉट, क्रिस्टोफ़. (2014 मार्च 28). क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय लोकतंत्र को बचा सकते हैं? कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस.
केजरीवाल, अरविंद. (2012). स्वराज. हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, इंडिया.
एनडीटीवी. (28 जनवरी, 2014). अरविंद केजरीवाल की सरकार का एक महीना: पांच हिट और पांच मिस. घोष, दीपशिखा (संपादक).
पार्टी विजन. (2013). आम आदमी पार्टी, ग्रेटर कैलाश.
सुब्रमण्यन, सामंत. (2013). द एजिटेटर. द न्यू यॉर्कर.
सेन, बिस्वरूप. (2016). समकालीन भारत में डिजिटल राजनीति और संस्कृति: एक सूचना-राष्ट्र का निर्माण। रूटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, न्यूयॉर्क।
आम आदमी पार्टी' के राष्ट्रीय संयोजक बने केजरीवाल, नवभारत टाइम्स, २६ नवम्बर २०१२, मूल से 29 नवंबर 2012 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि ११ दिसम्बर २०१३